

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./137/2016/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

1. श्रीमती ढेलकंवर पत्नी चंदनसिंह बनाम 1.मोहम्मद पुत्र माघा वगै.  
कायम मुकाम गुलाबसिंह वगै.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./138/2016/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

1. श्रीमती ढेलकंवर पत्नी चंदनसिंह बनाम 1.मोहम्मद पुत्र माघा वगै.  
कायम मुकाम गुलाबसिंह वगै.

अपीलांत का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री प्रेमराम सोनी प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 संख्या 06 की ओर से

**निर्णय**

दिनांक:- 14.11.2019



अधिवक्ता अपीलांत द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि उत्तरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद पेश किया उस वाद में वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 6 रकबा 173.08 बीघा में अपीलकर्तागण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा है तथा उत्तरदाता संख्या 01 का केवल 1/8 हिस्सा ही था जैसाकि खतौनी बंदोबस्त से साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना 3/4 हिस्सा भूमि की भूमि अपीलकर्तागण का होने से उनकी सम्पूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते में जरिये निर्णय दर्ज की गई। उत्तरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को जानबूझकर पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलांतगण पर्चा लगान के जागीरदार थे। खसरा बंदोबस्त में कॉलम संख्या 07 में खुदकाशत 3/4 दर्ज है। खतौनी बंदोबस्त में भी 3/4 चंदनसिंह के नाम दर्ज है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया। खसरा संख्या 06 का मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपीलांतगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील पेश करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलान्त को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारम्भिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलान्त का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। सेटलमेंट के समय भी अपीलान्तगण खातेदार नहीं थे। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्तगण का कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है। अपीलान्तगण के सेटलमेंट के समय काशतकारी नहीं थे वो जागीरदार के रूप में दर्ज थे। हमने हमारे हक के हिसाब से डिक्री करवाई है। गिरदावरी में अपीलान्तगण का नाम दर्ज नहीं है। अपीलान्तगण वादग्रस्त आराजी में यदि कोई अपना खातेदारी हक मानते तो संबंधित न्यायालय सहायक कलेक्टर में चाराजोही करते। अपीलान्तगण दूसरे के कंधे बंदूक रखकर न्याय पाने की चेष्टा कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत एवं प्रक्रिया के अनुसार किया है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व जमीन जागीरदारी रही, उस वक्त भूमिपति तत्कालीन जागीरदार होते थे जो सेटलमेंट व राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से उक्त कॉलम संख्या 3 में भूमिपति राज्य सरकार होने से उसी समय से ही भूमिपति राज्य सरकार दर्ज होता आ रहा है। वास्तव में जागीरदारों का अंकन एवं रिकार्डेड अधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के दिन से ही समाप्त हो गया था। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्त हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील



इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2018(2) Page 1112

RRT 2015(1) Page 696

RRD 2005 Page 305

RRD 2006 Page 379

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6 रकबा 173.08 बीघा भूमि पर जागीरदार दर्ज होने से अपना हक जताकर यह अपील पेश की गई। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात एवं साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्तगण का कब्जा काशत है। वक्त सेटलमेंट अपीलान्तगण

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर


जागीरदार के रूप में दर्ज है। सेटलमेंट के समय भी अपीलांटगण काश्तकारी के रूप में दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को लेकर मूल दावा पेश किया जो विचाराधीन है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना दावा साबित करते हैं तो वे अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किये हैं जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांटगण का हित प्रभावित होता हो।


इस कारण अपीलांटगण किसी भी रूप में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से सीधा प्रभावित/हितबद्ध या पीड़ित व्यक्ति नहीं है लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 46/2006 वादी मोहम्मद बनाम अलीयां में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2008, 27.10.2010 व 11.04.2011 को यथावत रखा जाता है।



यह आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
14/11/19  
(नाथूसिंह) अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

  
14/11/19  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर